



Nora Fatehi's
Fifa World Cup...

SHARE	
सेंसेक्स	: 73,983.18
निफ्टी	: 23,214.95

SARAFARAZ	
सोना	: 13,795
चांदी	: 260.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

40 हजार घूस लेते बैंक का एजेंट गिरफ्तार

RANCHI : रांची स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जमशेदपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सोनारी शाखा के एजेंट सलित भगत को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह एसबीआई, सोनारी की शाखा प्रबंधक जयबाला बिरुआ के नाम पर रिश्वत ले रहा था। शिकायतकर्ता से लोन के बदले रिश्वत की मांग की गई थी, रिश्वत नहीं देने पर उसके सेलरी अकाउंट को होल्ड कर दिया था। खाते से होल्ड हटाने के एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में रांची स्थित सीबीआई ने 7 जून को आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद सीबीआई बैंक मैनेजर जयबाला बिरुआ के विरुद्ध लगे आरोपों की भी जांच कर रही है। जांच में दोषी मिलने पर उनके विरुद्ध भी जाच एजेंसी कानूनी कार्रवाई करेगी। शिकायतकर्ता संदीप कुमार सोय सरायकेला-खरसावा जिले के कुवाई थाना क्षेत्र के मारंगहातु के रहने वाले हैं। उन्होंने 29 मई को सीबीआई में लिखित शिकायत की थी।

आज और कल हो सकती है बारिश, ऑरेंज अलर्ट

RANCHI : झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 11 और 12 जून को गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की संभावना बताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के प्रभाव और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे शरण न लेने तथा बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

राममंदिर के चढ़ावे में चोरी के दावे पर पीएमओ सख्त

RANCHI : अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी सूत्रों से पता चली है। भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। इधर, राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंगलवार को ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की थी। राम मंदिर परिसर के एक बंद कमरे में करीब 4 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में चढ़ावे की राशि, उसके उपयोग और लेखा-जोखा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को फिर से राम मंदिर में कथित चोरी का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने सरकार से 11 सवाल पूछे थे।

स्ट्रॉंग डिफेंस

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हाई टेक्नोलॉजी से लैस हुई इंडियन आर्मी

अपने रक्षा कवच को मजबूत बनाने में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा भारत

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : गुजरे 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और सुशासित नेतृत्व ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के विजन के परिणामों ने दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींचा है। डिफेंस सिस्टम को और सशक्त किया है। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ 7-8 मई को किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' ने सीमा पर आतंकवादियों के कई गढ़ों को नरसनाबुद कर दिया। इस कार्य को अंजाम देने में तीनों सेनाओं की समन्वित कार्य प्रणाली ने तब लक्ष्य को तय समय-सीमा में हासिल कर दुनिया को चौंका दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न कुछ परेशानियां ने तीनों सेनाओं को अब हाई टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया है।

तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय की कार्य प्रणाली ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि से उठाए गए कदमों ने सैन्य मनोबल को किया और सशक्त

उन्नत अग्नि मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण ने सिक्किम में टांगेरेट्टी टांगेरेट्टी री-घंट्री वहीकल चौतरफा मारक तकनीक से पूरी तरह लैस

नई अग्नि मिसाइल एक साथ कई अलग-अलग लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम

अपने साथ कई सारे हथियार या पेलोड एक ही समय में ले जा सकती है यह मिसाइल

एतिहासिक और शानदार कामयाबी, कठिन लक्ष्यों को आसानी से किया पार

पिछले एक साल में ही भारतीय रक्षा प्रणाली को उच्च तकनीक से लैस बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में हाल ही में भारत ने अपनी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी, ऐतिहासिक और शानदार कामयाबी हासिल की है। देश ने अपनी उन्नत अग्नि मिसाइल के एक बेहद खास और आधुनिक रूप का सफल उड़ान परीक्षण किया था। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि यह मिसाइल एनआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री वहीकल नाम की एक बेहद जटिल और चौतरफा मारक तकनीक से पूरी तरह लैस है। यह एक साथ कई अलग-अलग लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। रक्षा

NEW DELHI @ PTI :

बुधवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद भारत के लोगों ने देखा कि सही नीयत से सरकार चलती है तो देश का विकास होता है। 12 सालों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं। हमने सालों के काम महीनों में किए। मोदी ने कहा, 12 सालों में देश कांग्रेस के कूचक्र से आजाद हुआ। कांग्रेस ने देश को लाचार बना दिया था। देश को एहसास कराया था कि विकास धीरे-धीरे होता है और इसे हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था। विफलता कांग्रेस की थी, लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 सालों में जितना विकास हुआ, वह दशकों से क्यों नहीं हुआ।

2014 में 74 एयरपोर्ट थे, अब 160 से ज्यादा हैं। 12 साल में 1000 किमी एक्सप्रेस-वे से

6700 किमी एक्सप्रेस-वे हो गए। पहले 5 शहरों में मेट्रो थे। अब 20 शहरों में मेट्रो हो गए। 2014 में

भारत के लोगों ने देखा कि सही नीयत से काम करने पर देश का होता है विकास



भारत मंडपम में हुई मीटिंग में 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने लिया भाग।

मंत्रियों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर जताई खुशी

उल्लेखनीय है कि 10 जून को ही नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गौरतलब मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। बुधवार को उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। पीएम के तौर पर यह उनका मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का था। वे 1952



में हुए पहले आम चुनाव के बाद 4398 दिनों तक इस पद रहे। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर दोपहर 12.30 बजे केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। साथ ही एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया।

बैठक के बाद मोदी और भाजपा-एनडीए नेताओं ने खाई झालमुड़ी

सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शाम में भारत मंडपम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की बैठक हुई। इसमें भाजपा और एनडीए शासित शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम और अन्य नेता शामिल हुए। सभी ने पीएम मोदी को बधाई दी। उनका अभिनंदन किया बैठक के बाद मोदी और भाजपा-एनडीए नेताओं ने झालमुड़ी खाई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी ने पीएम को अपने हाथ से झालमुड़ी परोस कर दी। अप्रैल 2026 में बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाई थी। दुकान वाले से उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।



मोदी के लिए चारों धामों में हुई पूजा

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर लेकर चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में उनके नाम से विशेष पूजा-अर्चना की गई। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जलाभिषेक किया गया।

कुछ हो सकता है तो दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है।

टीएमसी में टूट जारी एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा

NEW DELHI : ममता बनर्जी की पार्टी तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में लगातार टूट जारी है। बुधवार को राज्यसभा सांसद सुमित देव ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। सभासित सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पिछले 3 दिनों में तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले 8 जून को सुखेंद्र शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी भी छोड़ दी थी। टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 सांसद और राज्यसभा में 13 में से 2 सांसद यानी कुल 22 सांसद टूट चुके हैं। 13 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतत गेट को अपना नेता बनाया है।

राज्यसभा चुनाव : नॉमिनेशन को लेकर उठी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद फैसला विवादों के बीच परिमल का नामांकन वैध घोषित

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी के नामांकन पत्र को रिवर्निंग ऑफिसर ने बुधवार को वैध करार देते हुए मंजूरी दे दी। नामांकन को लेकर उठी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही नथवाणी आधिकारिक तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अब राज्यसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल

कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने विधानसभा परिसर में जताया विरोध



नथवाणी के बीच मुकाबला होगा। राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है, ऐसे में चुनावी

सलमान को भाग लेने की नहीं मिली अनुमति

सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए दिल्ली से रांची पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुशीद को प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने विधानसभा परिसर में विरोध जताया। कांग्रेस कोटे की मंत्री शिल्पी नेहा ठीकी,

दीपिका पांडेय सिंह और राधाकृष्ण किशोर समेत अन्य नेताओं ने रिवर्निंग ऑफिसर कार्यालय के बाहर विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि नामांकन से जुड़े मामले में प्रवाशी की ओर से नया शपथ पत्र स्वीकार किया गया, लेकिन उनकी ओर से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारों को पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

समीकरण और भी रोचक हो गए हैं। 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि नामांकन पत्रों की जांच के

दौरान परिमल नथवाणी के नामांकन को लेकर कांग्रेस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

ईरान ने बहरीन, कुवैत व जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया अटैक



NEW DELHI @ PTI :

बुधवार को ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर कुल 21 हमले करने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि नुकसान की जानकारी बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही है। ईरान को इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्स (आईआरजीसी) ने कहा कि ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और निगरानी रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इससे पहले सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। एक दिन बाद ट्रंप ने इसका आरोप ईरान पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस हमले का जवाब जरूर देगा और

अमेरिका की ओर से की गई एयरस्ट्राइक के जवाब में लिया एक्शन

होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम व निगरानी रडार ठिकानों पर किए गए थे हमले

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले थे- हेलिकॉप्टर गिराने का लेंगे बदला

इसके जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान ने अमेरिकी हेलिकॉप्टर गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि मंगलवार रात ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया गया।

एमजीएम थाना क्षेत्र में महिला व परसूडीह में कान्वाई चालक को हमला कर मार डाला

BHAGALPUR : पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में बुधवार को एनएच-31 पर अजून कालोज के समीप सिलीगुड़ी से भागलपुर जा रही समीर देवस्स की बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में पांच यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि देवस्स सड़क सुबह करीब पांच बजे हुई। उस समय बस में खगड़िया, नवगछिया और भागलपुर जाने वाले कई यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग बस के भीतर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस का पिछला शीशा तोड़ा और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से पेंशन की राशि उनके खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के

गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर सिधे 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच जरूरतमंद लोगों को बेहतर आर्थिक सहाय मिल सके।

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य

तकनीक और डिजिटल समाधान के उपयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि तकनीकी सहयोग के माध्यम से जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है तथा राज्य के विकास को नई गति दी जा सकती है। गूगल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे भारत में उपलब्ध संभावनाओं और डिजिटल अवसरंचना के विकास में सहयोग को लेकर सकरात्मक रुचि दिखाई। बैठक के दौरान राज्य में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, निवाचन को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

AGENCY ARARIA : बिहार के अररिया जिले में बुधवार को रफ्तारार का कार देखने को मिला। अररिया पूर्णिया मुख्य मार्ग एनएच 27 फोरलेन सड़क पर हुए हादसे का साईकिल सवार सहित कुल चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। दरअसल कुसियारागांव बायोइंडवर्सिटी पार्क के पास तेज रफ्तार साईकियों अनियंत्रित होकर पहले साईकिल सवार को ठोकर मारी, जिससे साईकिल सवार गैरारी निवासी कोनेन अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्कॉर्पियो लेकर चालक तेजी से भागने लगा, जिससे स्कॉर्पियो अपना लेन छोड़कर दूसरे लेन में एक कार पर पलट लगे। जिससे स्कॉर्पियो में सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कार में सवार चार अन्य लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए

सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुक में पूर्णिया अमीर के विधानमण्डल निवासी गौतम झा, मानयन्द झा और शांति देवी हैं। सूचना के बाद सदर एसडीपीओ सुशील कुमार समेत नगर थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक सहित कुलिस अधिकारी और वल पुलिस मौके पर पहुँचकर जांच में जुट गए। मौके पर पहुँची पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। हादसे के कारण सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों का लंबा कपिल्ला लग गया है। जिसके कारण आवगमन ठप्प हो गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया, वहीं सड़क को खाली करवाकर आवगमन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।

AGENCY KISHANGANJ :
किशनगंज पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 367.8 ग्राम हेरोइन के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कुलीकोट थाना क्षेत्र के धर्मकाटा चौक स्थित एक कबाड़खाने में छापेमारी के दौरान की गई। पुलिस ने मौके से कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर गुप्त सूचना मिली थी कि धर्मकाटा चौक स्थित हजरत अली के कबाड़खाने में अवैध मादक पदार्थों का भंडारण तथा खरीद-बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस एच ए एसएसबी की संयुक्त टीम ने कबाड़खाने में छापेमारी की।

तलाशी अभियान के दौरान टीना ने कुल 362.8 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके अलावा 10 मोबाइल फोन, एक लाल रंग की हुंडई आई-10 कार (बीआर 11यू8677) तथा एक पस्टर मोटर साइकिल (बीआर37 एडी3915) भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके से कबाड़ाखाना संचालक हजरत अली, उनकी पत्नी तुमिना बीबी खातून, नाजीमूल हुसैन, मो. साकिर, वजीम अख्तर उर्फ राहुल शेख, बबू शेख तथा नेपाली निवासी नुरज आलम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश लोग पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार पृष्ठतालिका में दौरान आरोपियों ने कबाड़ाखाने के हेरोइन के भंडारण और उसकी खरीद-बिक्री में सलिलतला स्वीकार की है। जांच एजेंसियां अब इस गिरफ्त के साथ सदस्यों की पहचान करने के साथ-साथ बरामद हेरोइन के स्रोत और इसके वितरण नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है।

नूरज आलम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश लोग पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले बुढ़ाए गए हैं। गुलिस के अनुसार पताछ के दौरान आरोपियों ने कबाड़ाखाने में हेरोइन के भंडारण और उसकी खरीद-बिक्री में सौलिपता स्वीकार की है। अन्य एजेंसियां अब इस गिरफ्तार के बीच सदस्यों की पहचान करने के साथ-साथ बरामद हेरोइन के स्रोत और इसके वितरण नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं।

SARAN : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निदेशानुसार लिखा विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 11 जून को सैनिक कल्याण बोर्ड परिसर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूर्वाह्न 10:00 बजे से शुरू होने वाले शिविर का मुख्य विषय एम्पलप्लायमेंट वीर परिवार सहाय योजना 2025 है। इस कार्यक्रम उद्देश्य पूर्व सैनिकों, शहीद जवानों के आश्रितों और सैनिक परिवारों को उनके विधिक अधिकारों, सैनिक योजनाओं तथा नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों से अवगत कराना है। शिविर के संचालन के लिए विधि छात्रों और पंचा विधिक स्वयंसेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो मौफ़त ही विधिक परामर्श देंगे।

AGENCY KISHANGANJ :
किशनगंज मंडल कारा में बुधवार की अहले सुबह एक विचारार्थीन महिला बंदी द्वारा फांसी लगावया आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।
महिला बंदी ने कहित तौर पर जेल परिसर स्थित महिला शौचालय में दुपुष्टे का फंद बनाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर अवस्था में उसे इंडलाया के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जो जांच के बाद मृत घोसित कर दिया। मृतका की पहचान कोचाधामन थाना क्षेत्र निवासी लखारानी, पुई अजय प्रसाद सिन्हा के रूप में हुई है। वह फरवरी 2026 से देहज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत के

लोट्टर कफ सिरप जल्ट
SIWAN : उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़े कार्रवाई करते हुए गुजनी थाना क्षेत्र स्थित गुजनी चेक पोस्ट से भारी मात्रा में कोडीन फॉरसेट युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गुजरत नंबर के एक डीसीएम ट्रक की जांच की। जांच के दौरान हवान चालक की टीम को देखकर ट्रक रोककर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर ट्रक में रखे टायरों के भीतर छिपाकर रखी गई 1530 लोट्टर कोडीन फॉरसेट युक्त कफ सिरप बरामद की गई।

PHOTON NEWS PATNA : चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ 'खान सर' के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तब तक लिया है और

PHOTON NEWS KATIHAH : सीमांचल के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कटिहार के अनुसूचन कार्यालय परिसर में नवसृजित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा किया गया। इस कार्यालय के शुरू होने से अब कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले के नागपा 15

PHOTON NEWS SAHARSA : ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल करते हुए जिले के मिसरी बख्तियारपुर प्रखंड के सोहन पंचायत में मजरीया के सांख्यिक से निर्मित कृषिजिका दीदी का ग्रामीण हाटरे का बुधवार को उद्घाटन जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार एवं उप विकास आयुक्त

AGENCY KISHANGANJ :
किशनगंज मंडल कारा में बुधवार की अहले सुबह एक विचारार्थीन महिला बंदी द्वारा फांसी लगावया आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।
महिला बंदी ने कहित तौर पर जेल परिसर स्थित महिला शौचालय में दुपुष्टे का फंद बनाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर अवस्था में उसे इंडलाया के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जो जांच के बाद मृत घोसित कर दिया। मृतका की पहचान कोचाधामन थाना क्षेत्र निवासी लखारानी, पुई अजय प्रसाद सिन्हा के रूप में हुई है। वह फरवरी 2026 से देहज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत के

लोट्टर कफ सिरप जल्ट
SIWAN : उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़े कार्रवाई करते हुए गुजनी थाना क्षेत्र स्थित गुजनी चेक पोस्ट से भारी मात्रा में कोडीन फॉरसेट युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गुजरत नंबर के एक डीसीएम ट्रक की जांच की। जांच के दौरान हवान चालक की टीम को देखकर ट्रक रोककर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर ट्रक में रखे टायरों के भीतर छिपाकर रखी गई 1530 लोट्टर कोडीन फॉरसेट युक्त कफ सिरप बरामद की गई।

अचानक नाव में पानी भरने लगा और कुछ ही देर में वह नदी में पलट गई।
 पानी पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग नदी की तेज धारा में बहने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सात लोग कीर्ति तरह तेरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कुछ को ग्रामीणों ने सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। हादसे में चार लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है।

AGENCY SAHARSA : कोशी नदी के संभावित दबाव एवं वषाकाल को दृष्टिगत रखते हुए शेष सभी सुरक्षात्मक एवं अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अखिल्वर्ग पूर्ण करने को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार द्वारा सलगुआ प्रखंड अंतर्गत पूर्वी कोशी तटबंध के 117 किलोमीटर पर अवस्थित स्पर को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने स्पर की वर्तमान स्थिति का जांचवा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से संरचना की सुरक्षा एवं मजबूती के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने तटबंध एवं स्पर की नियमित निगरानी एवं सुरक्षा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण क्रम में कोशी

तटबंध का निरीक्षण करते जिलाधिकारी दीपेश कुमार व अन्य

नदी के संभावित दबाव एवं वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए शेष सभी सुरक्षात्मक एवं अनुरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। ताकि तटबंध की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। निरीक्षण के क्रम में

संबंधित विभाग के अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा संरचनाओं की सतत मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध रखरखाव पर विशेष बल दिया गया। जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार द्वारा सलखुआ प्रखंड

अंतर्गत स्थित स्लुइस गेट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्लुइस गेट की वर्तमान स्थिति, जल निकासी व्यवस्था एवं संबंधित संरचनाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उक्त अवसर पर उपस्थित संबंधित

विकसित भारत के निर्माण की राह

जब मैं तिरुपुर के स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते थे कि भारत अपनी महानता कब वापस पाएगा। हमारे गरीब और वॉचत भाई-बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा। मुझे खुशी है कि किशोरावस्था में मेरे मन में जो विचार थे, वे अब साकार हो रहे हैं। मैं अक्सर खुद को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। स्वामीजी के ये उद्गार हर व्यक्ति में देशभक्ति और समर्पण की भावना जगाने की अपार शक्ति रखते हैं। मेरा हमेशा यह विश्वास रहा कि जब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा, तब वह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनकर उभरेगा। अब हमें अपनी आंखों के सामने तिरुवल्लुवर के इन शब्दों की सच्चाई देखने का अवसर मिल रहा है, जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे ठीक वही हासिल करते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। पिछले एक दशक में मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हमारा देश जबरदस्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दौर की निरंतर विकास का युग बनाने के लिए सरकार और जनता दोनों का साझा उत्साह ही इस प्रगति का कारण है। एक समय कमजोर अर्थव्यवस्था माने जाने वाला हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा आर्थिक विकास समावेशी रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। अब तक भारत में गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। मैंने गांवों को इलाज की सुविधा न मिलने के कारण परेशान होते देखा है। उनके परिवारों की पीड़ा देखकर मुझे दुख होता था। आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। केवल पिछले एक वर्ष में ही 2.5 करोड़ लोगों ने इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। तीन करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बनकर अपना जीवन संसार चुकी हैं। महिलाओं के दैनिक जीवन को आसान बनाने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लगभग दो करोड़ नए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। नारी शक्ति चंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को और सशक्त बनाएगा। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों ने क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है। युवा शक्ति के लिए पिछले दस वर्षों में ही 13 नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं। आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 हो चुकी है। मेडिकल कालेजों की संख्या भी बढ़कर 823 हो गई है। यह गांवों की बात है कि मेडिकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,29,603 हो गई है। हम विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे का लगभग 99 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। वरें भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। हवाई अड्डों की संख्या भी 74 से बढ़कर 163 हो गई है और उड़ान योजना के तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है। नए पबन ब्रिज से लेकर चिनाव ब्रिज हो या बोगीबील पुल, भारत अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी भारत के अंतिम गांव माने जाते थे, वे अब देश के प्रथम गांव बन चुके हैं और वाइब्रेंट विलेज स्कीम के माध्यम से उनका विकास किया जा रहा है। चंद्रयान-3 की सफल लांचिंग ने भारत को उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान के नए युग में पहुंचा दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियां भारत को अपना केन्द्र बना रही हैं, जिससे निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक माडल बनकर उभर रहा है। मोबाइल फोन उत्पादन में भी हमने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। जो भारत कभी मोबाइल फोन आयात करता था, वही आज 300 करोड़ डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात करने वाला देश बन चुका है। ये सभी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव बनेंगी। कई दशकों तक देश ने केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि उग्रवाद और वामपंथी चरमपंथ जैसी चुनौतियों का भी सामना किया है। साहसिक नीतिगत फैसलों और कानून के सख्त पालन के माध्यम से आज देश में शांति स्थापित हुई है और इन क्षेत्रों में विकास के द्वार खुले हैं।

Social Media Corner

सब के हक में...

देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के खास सम्मान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। आपके कार्यकाल में शासन, आर्थिक मजबूती और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। कल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ ज्यादा समावेशी और समान रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचे, जो 'अंतर्वेद्य' के सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिद्वंदता को मजबूती से दर्शाता है। आपके नेतृत्व में शुरू की गई कई पहलों में से, पीएम-जनमर्भ और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपकी प्रेरणादायक यात्रा भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं में उम्मीद और नया आत्मविश्वास जगाती रहती है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं ताकि आप देश की सेवा करते रहें और इसे 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित भारत' के विजन की ओर ले जाएं।

(राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 'एक्स' पर पोस्ट)

श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने और अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे करने पर बधाई। 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित एक अथक कर्मयोगी के रूप में, उनका कार्यकाल भारत के प्रति अटूट समर्पण, देशवासियों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्प और राष्ट्र की सेवा में परिवर्तनकारी नेतृत्व को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत की जनता द्वारा उनके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और समावेशी विकास व सुशासन के लिए उनकी निरंतर कोशिशों का प्रमाण है।

(राजनाथ सिंह का 'एक्स' पर पोस्ट)

सादगी, संतुलन, आत्मीयता और प्रकृति के साथ सामंजस्य



डॉ. सत्यवान सौरभ

लकड़ी के मजबूत ढांचे और रिससों या पट्टियों से बुनी हुई यह संरचना सदियों तक भारतीय जीवन का आधार रही। गांवों में चौपाल की पहचान खातो से होती थी। परिवार के बुजुर्ग खाट पर बैठकर निर्णय लेते थे। किसान दिनभर के श्रम के बाद खाट पर विश्राम करते थे और बच्चे उसी पर खेलते-कूदते बड़े होते थे। यह केवल आराम का साधन नहीं थी, बल्कि सामाजिक संवाद का मंच भी थी। आज भी ग्रामीण भारत में खाट पर बैठकर होने वाली चर्चाएं लोकतांत्रिक संवाद की सबसे सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। पिछले कुछ दशकों में जीवनशैली में बड़े बदलाव आए। लोगों ने आधुनिक फर्नीचर को प्रगति और समृद्धि का प्रतीक मान लिया। बड़े-बड़े बेड, मोटे गद्दे और आकर्षक डिजाइन वाले फर्नीचर घरों की आवश्यकता बन गए। विज्ञापनों ने भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आराम केवल महंगे गद्दों और आधुनिक बिस्तरों में ही संभव है। परिणामस्वरूप खाट धीरे-धीरे घरों से बाहर होती चली गई। अब जब लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, बढ़ते तनाव और कृत्रिम जीवनशैली के दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं, तब वे उन पारंपरिक विकल्पों को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं जिन्हें कभी उन्होंने खय्य ही त्याग दिया था।

एक समय था, जब भारतीय घरों, आंगनों, चौपालों और खेतों में लकड़ी की खाट या चारपाई जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक खाट केवल एक फर्नीचर नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन का केंद्र थी। जैसे-जैसे आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा, शहरीकरण ने गति पकड़ी और बाजार में नए-नए प्रकार के बेड, सोफा-कम-बेड तथा महंगे गद्दे आने लगे, खाट धीरे-धीरे घरों से गायब होने लगी। इसे पुरातन, ग्रामीण और पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया गया, परंतु समय का चक्र एक बार फिर घूम रहा है। आज लोग दोबारा लकड़ी की खाट की ओर लौट रहे हैं। यह वापसी केवल एक पारंपरिक वस्तु की वापसी नहीं है, बल्कि जागरूकता और प्रकृति के साथ संतुलन की तलाश का प्रतीक भी है। भारतीय समाज में खाट का इतिहास बहुत पुराना है। इसे चारपाई, मंजी या खटिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। लकड़ी के मजबूत ढांचे और रिससों या पट्टियों से बुनी हुई यह संरचना सदियों तक भारतीय जीवन का आधार रही। गांवों में चौपाल की पहचान खाटों से होती थी। परिवार के बुजुर्ग खाट पर बैठकर निर्णय लेते थे। किसान दिनभर के श्रम के बाद खाट पर विश्राम करते थे और बच्चे उसी पर खेलते-कूदते बड़े होते थे। यह केवल आराम का साधन नहीं थी, बल्कि सामाजिक संवाद का मंच भी थी। आज भी ग्रामीण भारत में खाट पर बैठकर होने वाली चर्चाएं लोकतांत्रिक संवाद की सबसे सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। पिछले कुछ दशकों में जीवनशैली में बड़े बदलाव आए। लोगों ने आधुनिक फर्नीचर को प्रगति और समृद्धि का प्रतीक मान लिया। बड़े-बड़े बेड, मोटे गद्दे और आकर्षक डिजाइन वाले फर्नीचर घरों की आवश्यकता बन गए। विज्ञापनों ने भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आराम केवल महंगे गद्दों और आधुनिक बिस्तरों में ही संभव है। परिणामस्वरूप खाट धीरे-धीरे घरों से बाहर होती चली गई। अब जब लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, बढ़ते तनाव और कृत्रिम जीवनशैली के दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं, तब वे उन पारंपरिक विकल्पों को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं जिन्हें कभी उन्होंने स्वयं ही त्याग दिया था।



लकड़ी की खाट की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। आधुनिक जीवनशैली में कमर दर्द, गर्दन दर्द और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। बहुत अधिक जागरूकता और प्रकृति के साथ संतुलन की लिए, असुविधाजनक साबित हुआ है। इसके विपरीत खाट का ढांचा शरीर को संतुलित सहारा देता है। रिससों से बुनी खाट शरीर के भार को समान रूप से वितरित करती है, जिससे रीढ़ पर आनावश्यक दबाव कम पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक बुजुर्ग वर्षों तक खाट पर सोने के कारण बेहतर शारीरिक स्थिति में दिखाई देते हैं। यद्यपि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताएं अलग होती हैं, फिर भी खाट को प्राकृतिक और संतुलित विश्राम का साधन माना जाता है। गर्म जलवायु वाले हमारे देश में खाट की उपयोगिता और भी अधिक है। फोम और स्प्रिंग वाले गद्दे अक्सर शरीर की गर्मी को रोक लेते हैं, जिससे गर्मियों में असुविधा बढ़ जाती है। इसके विपरीत खाट के नीचे और ऊपर दोनों ओर से हवा का प्रवाह बना रहता है। यह प्राकृतिक वेंटिलेशन शरीर को ठंडक प्रदान करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। बिजली की बढ़ती खपत और एयर कंडीशनर पर निर्भरता के इस दौर में खाट का यह गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी खाट का महत्व बढ़ रहा है। आज दुनिया टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है। आधुनिक फर्नीचर उद्योग में प्लास्टिक, सिंथेटिक फोम और रासायनिक पदार्थों का व्यापक उपयोग होता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत लकड़ी और प्राकृतिक रिससों से बनी खाट अपेक्षाकृत पर्यावरण-अनुकूल होती है।

हाती है। यह लंबे समय तक चलती है। आसानी से मरम्मत की जा सकती है और इसके अधिकांश हिस्से पुनर्क्रियित या प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकते हैं। ऐसे समय में जब लोग पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, खाट उन्हें एक टिकाऊ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगी है। खाट की वापसी का एक कारण आर्थिक भी है। महंगे फर्नीचर और ब्रांडेड गद्दों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई खाट अपेक्षाकृत सस्ती और टिकाऊ होती है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आज भी खाट कम लागत में उपलब्ध है। यह वर्षों तक उपयोग में आ सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रिससयां बदलकर उसे फिर नया बनाया जा सकता है। इस प्रकार खाट केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहारिक विकल्प है। दिलचस्प बात यह है कि खाट की वापसी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बड़े शहरों में भी लोग इसे नए रूप में अपना रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनरों ने सांस्कृतिक खाट को आधुनिक सौंदर्यबोध के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया है। आज कई घरों में खाट को बालकनी, गार्डन, टैरेस या लिविंग स्पेस में सजावटी और उपयोगी वस्तु के रूप में रखा जा रहा है। रिसॉर्ट, कैफे और होमस्टे भी अपने परिसर में खाट का उपयोग कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों को देसी और पारंपरिक अनुभव मिल सके। यह दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता का मेल किस प्रकार संभव है। सोशल मीडिया ने भी खाट की लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सस्टेनेबल लिविंग, स्लो लाइफ़, देसी लाइफ़स्टाइल और रूट्स की ओर वापसी जैसे

विषय युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग अपने घरों और फार्म हाउस में खाट के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। अनेक युवा, जो कभी खाट को केवल गांवों की वस्तु मानते थे, अब उसे जीवनशैली और प्रवेशन का हिस्सा समझने लगे हैं। यह परिवर्तन बताता है कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए नजरिए से देख रही है। खाट का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। भारतीय साहित्य, लोकगीतों और फिल्मों में खाट का उल्लेख बार-बार मिलता है। यह ग्रामीण जीवन, आत्मीयता और सामूहिकता का प्रतीक रही है। जब परिवार के सदस्य एक साथ खाट पर बैठकर बातचीत करते थे, तब संवाद स्वाभाविक रूप से विकसित होता था। आज डिजिटल युग में जहां लोग एक ही घर में रहते हुए भी मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं, वहां खाट जैसे सामूहिक बैठने के स्थान फिर से सामाजिक निकटता का माध्यम बन सकते हैं। हालांकि खाट की वापसी का अर्थ यह नहीं है कि आधुनिक फर्नीचर पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। आधुनिक जीवन की आवश्यकताएं अलग हैं और कई परिस्थितियों में आधुनिक बेड अधिक सुविधाजनक भी हो सकते हैं। लेकिन, खाट की बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत अवश्य देती है कि लोग केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी महत्व देने लगे हैं। वे ऐसे विकल्प खोज रहे हैं, जो जीवन को अधिक संतुलित और स्वाभाविक बना सकें। वास्तव में खाट का पुनरागमन उस व्यापक सामाजिक बदलाव का हिस्सा है जिसमें लोग अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे पारंपरिक भोजन हो, जैविक खेती हो, मिट्टी के बर्तन हों या लकड़ी की खाट लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि विकास का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं है। विकास का वास्तविक अर्थ उन परंपराओं को भी समझना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और जिनमें जीवन को सरल, स्वस्थ और संतुलित बनाने की क्षमता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और जीवन पहले से अधिक जटिल होता जा रहा है, तब लकड़ी की खाट हमें सादगी का संदेश देती है। वह याद दिलाती है कि आराम केवल महंगे साधनों से नहीं, बल्कि प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली से भी प्राप्त किया जा सकता है।

समकालीन साहित्य और स्मृतियों का साक्ष्य

लोक में जो संकेत, आत्मीय रचाव और सहज संचरणशीलता है, वह अतिआधुनिकता में भी स्वीकार्य है, उपयोगी है। लोक-रचनात्मकता का आधारपरक कार्य लोककला की कलात्मक एकता है। अतीत का उपयोग वर्तमान की आलोचना के बिना संभव नहीं। बिना आकांक्षा के न तो जीवन जिया जा सकता है और न ही कविता या साहित्य की रचना संभव है। समकालीन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है- स्मृतियों का साक्ष्य। स्मृतियां समकालीनता के विविध उपकरणों के समाहार से असंबद्ध नहीं रह सकतीं। हालांकि तार्किकता, परिवर्तनधर्मिता, शिल्प वैशिष्ट्य, गद्यपरकता इत्यादि सांक्षिप्तताओं से आकार ग्रहण करता समकालीन साहित्य स्मृतिविहीन नहीं हो सकता, फिर भी लोकानुख्याता लगातार क्षीण होती गई है। स्थानीयता का पुट विविध रंगों के साथ जैसे उभरने चाहिए, उसमें कमी आती दिख रही है। कुछ कवियों व उपन्यासकारों ने मौखिक

परंपराओं व धरती के उन्मुखीकरण को आधार बनाने का यत्न किया है, तो कुछ लोक को नए सिरे से समझ कर लाना चाहते हैं। कुछ कला और समुदाय के बीच के संबंधों से काम करते हैं, तो कुछ लोकप्रिय रूपों व ध्वनियों के आधार पर। कुछ सामाजिक आवेग को लोक संस्कृति में समंजन करके नई भाषा रच रहे हैं, तो कुछ काल्प-अन्धास से लोक कविता की संभावनाओं के लिए नई सदी में नए दृष्टिकोण से सक्रिय हैं। लोक संस्कृति की प्रमुख आधार प्रकृति महागंगों से जैसे ओझल हुई है, उससे लेखन-सूत्र की दशा बदल गई है। प्रकृति, नदी, पर्यावरण में जैसी स्मृतियां रही हैं तथा साहित्य की धारा का भी जैसे गोमुख्य रहा है, नगरीकरण की स्थिति के चलते (अब हिन्दी साहित्य भी नगरीकरण का प्रतीक होने लगा है) स्वयं के संदर्भ बदल गए हैं। यह सारा स्वयं छंदसुकृता की प्रयोजनता और वाक्यांशों की विविधताओं से भी पता चलता है। लोक की रचियां व अनेक जड़ताओं को साहित्य में जायज

नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन उसकी तरलता या प्रवाहमयता या सुगंध का खोना स्मृति-रहित होने जैसा ही है। साहित्य का नगरीकृत होना एक फेज है, लेकिन पारंपरिक अनुगूंजों से वंचित होना दूसरी बात। स्थानीयता के कई तरह के खतरे भी हैं, किंतु उसकी अलग आभा उसकी शक्ति भी है। प्रौद्योगिकी को स्थानीयता में खास व्यवहार मिलता है। साहित्य में स्थानीय संस्कृति को रचना एक खास सम्मोहन को शब्द देना है। उस सम्मोहन में एक गति भी होती है। कलात्मक प्रासंगिकता का दृश्यात्मकता व सांगीतिक अनुगूंजों से विशिष्ट संबंध है। इसीलिए लोक में जो दृश्यबंध आते हैं, उन्हें साहित्य में एक आकार दिया जा सकता है। यह अलग बात है कि समकालीनता के तनावों व लोक के समंजन का आधार क्या बनेगा या बना चाहिए, यह विचार व अनुप्रयोग का विषय है। नए-नए विषयों को उठाते हुए मिथक व लोक का समकालीनीकरण संभव है। कथा व कविता में तो यह

विशिष्ट आकार ले ही सकता है। यदि नगरीय जीवन की संपुक्ति में लोक कविता की मूर्धन्यता को समझा जाए तो कुछ अनुभव एकत्र किए जा सकते हैं। उससे प्रस्तुति व शैली में निश्चित भिन्नताएं आएंगी। लोक संगीत के लिए यू ट्यूब के रूप में एक नया आधार मिला है। सामूहिक कलात्मक गतिविधि, सामाजिक काम, रोजमर्रा की जिंदगी, जीवन व प्रकृति के ज्ञान, धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों को साहित्य में ढाल पाना इकहरा कार्य नहीं। लोक-रचनात्मकता का विशिष्ट आधारपरक कार्य लोककला की कलात्मक एकता है। लोक कला समाज के निचले तबके की आवश्यकताओं की उपस्थितियों के लिए निर्मित होती है। इसमें एक तरह का घरेलूपन है। चाहें तो उसकी पुरातनता में एक नवाचार भी ला दें। कविता में पुरातनता में नवसंभनन उसका महत्वपूर्ण पक्ष है। लोक में जो संकेत, आत्मीय रचाव और सहज संचरणशीलता है, वह अति आधुनिकता में भी स्वीकार्य है, बल्कि बहु उपयोगी।

अतीत का उपयोग वर्तमान की आलोचना के बिना संभव नहीं। बिना आकांक्षा न तो जीवन जिया जा सकता है और न ही कविता या साहित्य की रचना संभव है। लोक को सस्ते फैशन परस्ती के रास्ते पर ले जाने, उसे उपभोक्तावादो सिस्डम में खपाने और तदनुकूल साहित्य के सरलीकरण को स्तरहीनतापूर्वक बल देने की भी कोशिशें जारी हैं। यह ऐसा प्रश्न है, जो हमारे मानसतंत्र को बहुत बारीकी से झकझोरता है। जो लोकगीत अपने एक आम अतीत की रचनात्मक अभिव्यक्ति व समकालीन चेतना से जुड़ा है, उसे बाजार की इच्छाओं की झोंक में सौंपा जा रहा है। बाजार से सहयोग लेना बुरा नहीं, बाजार में जाना भी सही है, किंतु उसके तंत्र का अनुकर्ता मात्र हो जाना मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, जबकि साहित्य और लोक के अंतरसंबंध किसी भी अन्य अनुशासन की तरह हमें स्वयं को बेहतर और दूसरों को समझने के लिए सक्षम बनाते हैं। सारा मनोविज्ञान व समाजशास्त्र लोक

विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए नया प्रोटोकॉल

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किसी न किसी मामले के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नेपाल में जेन-जी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनने से लेकर चुनावों में शानदार प्रदर्शन तक उनका नाम छाया रहा। युवाओं ने उन पर भारी भरोसा जताया और उनकी विजय से ऐसा माना गया कि वे नेपाली राजनीति के पुराने एवं कमजोर किले को तोड़कर एक नवयुगीन भव्य इमारत का निर्माण करेंगे, जिसके स्तंभ प्रष्टाचार और विदेशी प्रभाव से अलग पारदर्शिता और संप्रभुता से ओतप्रोत होंगे। पिछले दो महीनों में इस दिशा में उन्होंने कुछ बड़े नीतिगत बदलाव भी किए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन प्रोटोकाल और सामान्य शिष्टाचार की व्यवस्था से जुड़ा है। प्रोटोकाल में उनका अग्रह है कि वे अपने समकक्ष विदेशी पदधारकों से ही मुलाकात करेंगे। ज्ञात हो कि पिछली सरकारों में प्रधानमंत्री प्रोटोकाल की इस परंपरा के पालन में विफल रहे, जिसके चलते उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। बालेंद्र शाह इस परिपाटी को बदलना चाहते हैं। परिवर्तन के इसी क्रम में बीते दिनों उन्होंने नेपाल आए कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और विशेष दूतों से भी मिलने से इस्लिफ इन्कार कर दिया, क्योंकि वे उनके पद और प्रोटोकाल में बराबर नहीं थे। इन विशिष्ट अतिथियों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर भी शामिल थे। गोर को शाह के मंत्रिमंडल के

सदस्यों से ही मिलकर लौटना पड़ा। वहीं मीडिया में आई खबरों की मांनें तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री का नेपाल दौरा नई दिल्ली ने इसी कारण स्थगित कर दिया, क्योंकि शाह से भेंट का कार्यक्रम नहीं बन पाया, जिसके पीछे भी प्रोटोकाल वाली परंपरा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन निर्णयों का नेपाली मीडिया और राजनीतिक विश्लेष पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन शाह के दृष्टिकोण से देखें तो वे वही कर रहे हैं, जिसका वादा उन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था। वह दर्शाना चाहते हैं पिछली सरकारें वादे तो करती रहीं, पर अमल नहीं कर पाई, विशेषकर विदेशी दबाव से निपटने में और विदेश नीति को निष्पक्ष रखने में। चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री बने दो महीने ही हुए हैं, इसलिए शाह चाहेंगे कि विदेश नीति के स्तर पर कोई ऐसा कदम न उठाएँ, जिससे किसी एक देश विशेष के प्रति उनका झुकाव दिखाई दे। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने विदेशी राजनयिकों के साथ अप्रैल में एक बैठक की, जिसमें भारत और चीन समेत पंद्रह अन्य देशों के राजदूत भी शामिल थे। यह पहला अवसर था जब किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम उठाया जो अग्रे पड़ोसी देशों जैसे भारत या चीन के राजदूतों से निजी स्तर पर भेंट न की हो। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री शाह नीतिगत बदलावों की दिशा में ऐसे कदम उठा रहे हैं। एक ओर जहां वह विदेशी सन्निकता के मोर्चे पर नए प्रोटोकाल बना रहे हैं, तो स्थापित घरेलू प्रोटोकाल की परंपरा को भी तोड़ रहे हैं। बीते दिनों जब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे, तो शाह ने बहिर्गमन किया जो प्रोटोकाल के हिसाब से बहुत खराब उदाहरण रहा। इसकी चर्चा नेपाली मीडिया में भी हुई। यह बात सही है कि हर सरकार को अपनी नीतियों और नियमों में बदलाव लाने का अधिकार है, लेकिन शाह का रवैया यही जाहिर करता है कि उनका जोर वैसे कदम उठाने पर ही अधिक है, जो उन्हें अलग तरह के नेता की छवि प्रदान करें। विदेश नीति और कूटनीति के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक ऐसी शुरुआत है, जिसका खामियाजा निकट भविष्य में नेपाल को जरूर भुगतना पड़ सकता है। यह न भूला जाए कि नेपाल भारत और चीन से घिरा हुआ देश है और नगमाम मामलों में वह भारत जैसे देश पर अपनी आर्थिक और व्यापारिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से निर्भर है। इतिहास भी साक्षी रहा है कि नेपाल पर जब भी कोई संकट आया है, तब भारत एक मित्र राष्ट्र के चलते प्रथम मददगार की तरह खड़ा रहा है। ऐसे किसी साझेदार को लेकर अगर नेपाल की सरकार प्रोटोकाल की दुहाई देना शुरू करेगी तो संभव है कि कोई सहाराता मांगने पर दूसरा पक्ष भी इसकी आड़ ले। नेपाल के नीति-निर्णयता यह भी न भूलें कि विशेष दूत हमेशा अपनी सरकार के हितेषी और नेता के संरक्षणवाहक होते हैं, जो दोनों पक्षों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं।

ईंधन की कीमतें

बीते चंद दिनों के अंदर पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्धि यही बताती है कि तेल कंपनियों के लिए उनके दाम स्थिर रखना संभव नहीं रह गया है। पेट्रोल-डीजल के साथ गैस के दाम इम्पीरिएल बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच टकराव के चलते वह होमुज समुद्री मार्ग बाधित है, जहां से विश्व के पांचवें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। चूंकि भारत अपनी आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक ईंधन आयात करता है, इसलिए उसके सामने पेट्रोल-डीजल-गैस के दाम बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो मजबूरी भारत के समक्ष आ खड़ी हुई है, वही विश्व के अन्य देशों के सामने भी है। इसकी अनदेखी न की जाए कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में कहीं बाद में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए। पेट्रोल-डीजल और गैस के बढ़ते दामों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि तेल, उर्वरकों और विदेशी मुद्रा पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है, उसकी पूर्ति तो सरकार को स्वयं ही करनी होगी। आम जनता इतना अवश्य कर सकती है और उसे करना भी चाहिए कि कफायत बरतने के उन उपायों पर ध्यान दे, जो सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए हैं। लोगों को यथासंभव इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों से विदेशी मुद्रा पर बोझ न बढ़े। वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ईंधन के साथ उर्वरकों की कीमतें अकल्पनीय रूप से बढ़ रही हैं और इसी के दाम भी चुनौती बन गए हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले दिन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यह वित्त मंत्री के इस कथन से और भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया संकट का असर जियो-पालिटिक्स से कहीं आगे तक जाता है और कारोबारियों एवं आम लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है-ईंधन की ज्यादा कीमत, कार्गों में देरी, शिपिंग का महंगा होना, इनपुट की अधिक लागत और निर्यात आर्डर में अनिश्चितता। उन्होंने यह भी कहा कि जरा सोचिए, जब ये सभी चीजें एक साथ सामने आए जाएं, तो क्या होगा?

Op Bluestar’s unfinished lessons for Punjab

Ramesh Inder Singh

The devout view it as a premeditated sacrilegious assault on their holiest of holy shrines while the government of the day described it as an operation to clear the sacred space of the armed radicals who had usurped the temple, laid siege and posed a challenge to the legitimacy of the constitutionally established polity.But with time and better understanding of the events, there is a near unanimity that the operation was avoidable, ill-planned and terribly executed. It left deep psychological scars, resulted in the destruction of the seat of Miri Piri, Akal Takht, and the death of nearly 1,000 persons, including Army men. And this unanimity of opinion includes a long list of army generals, including two former Army Chiefs, Gen VK Singh and Gen VN Sharma, who have gone public against Operation Bluestar.The operation that was launched to eliminate violence, in fact, sowed the seeds of an ethno-religious struggle and unleashed unmitigated violence that was far worse than what it had aimed to end. Foreign powers exploited our internal situation. Weapons and drugs seeped in from the highly porous border and confirmation of this has come from a Pakistani scholar. Prof Ilyas Chattha, in his book, ' The Punjab Borderland, Mobility, Materiality and Militancy, 1947-1987', has exposed the role played by his country in fuelling militancy in Punjab.

The ethno-national movement fizzled out long ago, but there are lessons to be learnt. The foremost lesson pertains to how we deal with religious plurality, political divergence, regional aspirations and uprisings. Regional assertions have to mingle with national objectives just as the nation must acknowledge the divergence of identities and aspirations in a country as large as ours.This requires not a military approach to problems but conflict resolution through dialogue. Bluestar is a classic instance of the failure to parley, even though 26 meetings were held between Dharam Yudh Morcha leaders and the Central government, the last being on May 29, 1984 with four Union ministers in Delhi. They responded positively to the demands, not knowing that the Chief of Army Staff, Gen AS Vaidya, had already been mandated a few days earlier that troops be moved to Amritsar. The result was catastrophic.

The irony is that these very demands of the Morcha were accepted a year later, in July 1985, with the signing of the Rajiv-Longowal accord. But, by then, the moderate Longowal and his ilk had ceased to be relevant. The command of the struggle had passed on to gun-wielding militants. The spirit of shaheedi swept the Panth.

To make it worse, the Central government ducked the accord — the PM who had signed the covenant discarded it. Political imperatives prevailed over the need for conflict resolution. The pending demands continue to agitate the state.

Could militancy re-emerge in the state? It is highly unlikely. However, microscopic remnants of secessionists sitting abroad continue to fund and direct criminal activities, operating through organised criminal gangs. It is a nexus of drugs and weapon smugglers, who often operate under the ideological garb of separatism.

The consequence of this is a deteriorating law and order situation, with cases of extortions, IED or grenade blasts, killings and frequent email threats of bomb scares at public places. Forces from across the border are using drones to drop weapons and drugs to destabilise the region.

However, the recent killings of three policemen in two separate incidents in the border districts are alarming, suggestive of what is called a consternation strategy, which terrorists apply to produce a chilling effect to demoralise the symbols of state authority. They randomly pick up targets with the objective to make the state appear ineffective.

Unlike Anna Hazare protest, CJP is about opportunity

The real story is about citizens and their aspiration and trust

Harvinder Khetal

WHEN the founder of the Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, mounted the stage at New Delhi's Jantar Mantar on Saturday, he was joined by an unlikely ally. Standing beside him was Sonam Wangchuk — education reformer, environmental activist and one of the country’s most respected public figures. Thousands of young protesters wearing cockroach masks cheered as the two addressed a gathering that had begun as an internet meme and evolved into a national conversation about jobs, examinations and the future of India's youth.They rallied under the banner of the CJP, a formation that did not exist a month ago. What began as a social media joke has become one of the most talked-about political phenomena in the country. The temptation is to dismiss the movement as another fleeting internet sensation.However, that would be a mistake. movements often matter less for what they ultimately achieve than for what they reveal. The sudden rise of the Cockroach Janta Party has revealed a generation that feels unheard. Beneath the headlines celebrating India's economic growth lies a growing reservoir of frustration about jobs, competitive examinations, social mobility and the perceived indifference of institutions. The movement has also demonstrated how satire can become a powerful political tool when conventional channels of representation appear ineffective.The image of young Indians marching under the banner of a cockroach serves as a warning. Democracies function best when citizens believe that hard work will be rewarded, opportunities will remain accessible and public institutions will act fairly. When that faith weakens, satire turns into protest and mockery acquires political force.

The developments in Delhi should also be viewed in a broader regional context. Across South Asia, Generation Z is emerging as a disruptive political force. In Bangladesh, student-led protests evolved into a wider challenge to established authority. In Nepal, youth-driven campaigns have increasingly mobilised around corruption, governance failures and economic stagnation, often bypassing traditional political parties. A common sentiment is visible: young people are no longer willing to wait for institutions to address their concerns.India's Cockroach Janta Party may be the latest expression of that sentiment. The CJP's rise is remarkable because of its simplicity. The movement emerged from a controversy in which unemployed youth were allegedly likened to "cockroaches" and

"parasites" by the Chief Justice of India Surya Kant. Instead of rejecting the insult, young Indians appropriated it. The slogan 'Main Bhi Cockroach' spread rapidly across social media platforms. The symbolism proved irresistible. Cockroaches survive hostile environments. They endure neglect. They are difficult to eliminate. For millions of students and job-seekers navigating repeated examination controversies, delayed recruitments and uncertain career prospects, the metaphor resonated.For many young Indians, success depends on clearing highly competitive tests. Yet



recurring reports of paper leaks, cancelled examinations, recruitment delays and legal disputes have eroded trust in the system. Every cancelled exam represents lost months or years of preparation. It means deferred careers, postponed marriages and mounting financial burdens on families.

This frustration is unfolding against a paradoxical backdrop. India is among the world's fastest-growing major economies. Government officials frequently highlight infrastructure expansion, digital innovation and rising global influence. But economic growth and opportunity are not always experienced in the same way. Aggregate growth figures conceal uneven outcomes. For many graduates, especially those outside elite institutions, the promise that education guarantees upward mobility appears increasingly uncertain.

That uncertainty explains why the CJP's message has travelled far beyond social media. The movement has given expression to a sentiment that political discourse overlooks. India's debates are frequently dominated by

Manipur crisis : Humanitarian tragedy must not be normalised

More than 43,000 people are living in temporary shelters and relief camps, many without proper healthcare, sanitation or psychological support

THE restoration of peace and normalcy in Manipur continues to be a Herculean task. As per details disclosed under the Right to Information Act, at least 730 internally displaced people have died in the northeastern state's relief camps since the outbreak of ethnic violence in May 2023. The high death toll is a damning indictment of the BJP-led Central and state governments. Tens of thousands of families have been uprooted by the conflict; they face an uncertain future as rehabilitation is nowhere in sight. Unfortunately, the humanitarian crisis has received scant national attention. More than 43,000 people are living in temporary shelters and relief camps, many without proper healthcare, sanitation or psychological support. The fact that camp residents are dying not only from illness but also from unnatural causes — including drowning, electrocution, substance abuse and violence — shows that the living conditions are both unsafe and sub-human.Four months after the



reinstatement of an elected government, there is no let-up in the attacks and ethnic hostility despite repeated assurances from the authorities. Three persons were

questions of nationalism, religion, caste alignments and electoral strategy. While these issues matter, they do not fully address the concerns of a generation preoccupied with securing stable employment and a dignified future.The comparison with the anti-corruption movement led by Anna Hazare is inevitable. Both emerged outside traditional party structures. Both relied heavily on youthful participation. Both reflected widespread dissatisfaction with existing institutions. The differences are equally revealing. The Hazare movement was about governance and corruption.

The Cockroach Janta Party is about opportunity. Fifteen years ago, young Indians demanded cleaner politics. Today, many are demanding a fair chance to compete, work and prosper. The shift speaks volumes about the changing socio-economics.

In 2011, when the Anna Hazare movement captured the national imagination, India's economy was worth about \$1.87 trillion and it was grappling with 9% inflation, slowing growth and allegations of policy paralysis. Today, the economy exceeds \$4 trillion, growth is among the fastest in the world, inflation is relatively moderate, digital infrastructure has expanded dramatically and India's global standing is considerably higher.For a country where 65% of the population is below the age of 35, the quality and accessibility of opportunities matter as much as headline growth figures.

At the same time, the movement's strength may also prove to be its weakness. Social media

can create visibility but not necessarily durability. Online movements often generate extraordinary enthusiasm only to dissipate when confronted with organisational realities. Building a sustainable political platform is a challenging task.The CJP must thus confront these questions: can symbolism be converted into substance? Can viral popularity evolve into meaningful reform? Can the movement develop a coherent agenda without losing its appeal?

These questions remain unanswered. But they do not diminish the movement's significance.For democracies, the most consequential political developments are often those that expose hidden anxieties. The CJP has exposed one such anxiety.

The real story, then, is about citizens and their aspiration and trust. Democracies function best when citizens believe that hard work will be recognised, rules will be fairly enforced and institutions will serve the public good. When that faith weakens, satire becomes protest and even a cockroach can become a political symbol.

India-EU tie has a Pak feeling

Juxtaposition of J&K and Ukraine war in Pak-EU statement strikes a jarring note

Vivek Katju

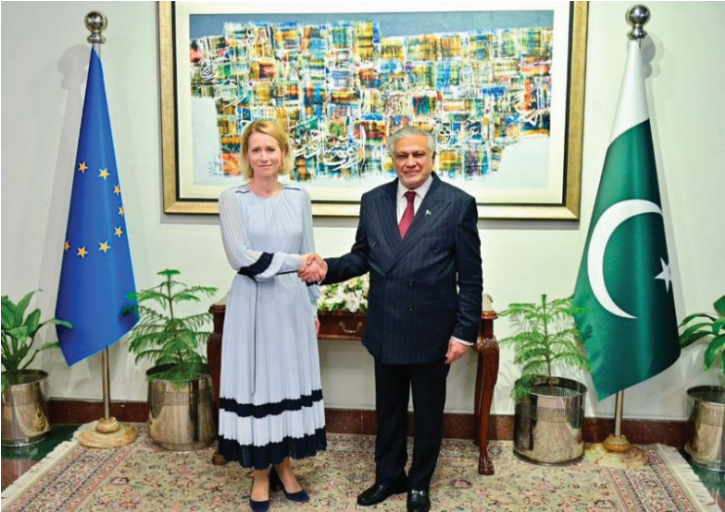
JUST when Indian policymakers thought that India-EU ties were on an upward trajectory, they received a rude shock. Standing beside Pakistan’s Foreign Minister Ishaq Dar in Islamabad on June 1, EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, said: “Pakistan is a major regional power and an important partner for the European Union”.Praising Pakistan’s mediation between the US and Iran, she said: “Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions, and these efforts are much recognised and appreciated across Europe”. This would have been music to Pakistani ears and jarring to some circles in Delhi, for there has been no change in Pakistan’s reliance on terrorism to keep India on the defensive.Paragraph 11 of the EU-Pakistan joint statement, which came out after Kallas’ discussions with Dar was unprecedented and offensive. It stated: “The Pakistan side briefed on the issue of Jammu and Kashmir. The EU side briefed on Russia’s war on Ukraine. Both sides expressed support for the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy in accordance with the principles of the UN Charter.”Prima facie, these lines are innocuous, but it is the juxtaposition of J&K and the Ukraine war that gave them an entirely different complexion. The skilled and professional EU diplomats who negotiated the joint statement would have known that putting J&K and the Ukraine war in the same paragraph would be unacceptable to India. Moreover, by joining the two issues through a sentence containing homilies on “dialogue and diplomacy” and invoking the UN Charter, they only added insult to injury. If the diplomats had slipped, why did Kallas do so too?

Kallas was Estonia’s Prime Minister for three years and has held her present office since December 2024; hence, she does not lack experience. The inescapable conclusion, therefore, is that the EU deliberately agreed to a formulation which the Pakistanis may have proposed. In accepting it, the EU showed complete disregard for Indian sensitivities.Lest some readers think that this writer is getting carried away by unimportant minutiae of diplomatese, a peep into the arcane world of diplomatic drafting is called for. Diplomats endeavour to find common formulations for joint statements. When they fail and one side insists that unless its views are recorded it will not agree even to a mention of a matter of surpassing importance to the other, unilateral statements are framed. They indicate that the other side has merely heard the view of the other. However, in recording these formulations, it is ensured that no link can be drawn between the unilateral comments. These inevitably come about if they are included in a single paragraph.

At present, it was naturally essential for the EU to mention the Ukraine war in a joint statement. In turn, the Pakistanis would have demanded the inclusion of their viewpoint on J&K. Even while accepting such a compromise, the EU should have insisted that J&K and Ukraine be mentioned in separate paragraphs. And, while diplomacy was being urged for J&K, the EU should have called for the right conditions being created by the cessation of cross-border violent extremism. The EU did not do so.Responding to a question on the reference to J&K in the joint statement, the Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson said on June 2: “We categorically reject such unwarranted references in the joint press communicate on matters internal to India. The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and

inalienable parts of India. Those who have no locus standi on such matters should desist from making any comment on them”. This was a routine and weak response to an unprecedented and unjustified paragraph in the joint statement. Why did the MEA not even mention the EU, let alone strongly condemn it?

Is it because the Modi government did not want the focus to be on its embarrassment? It had done the EU the high



honour of inviting Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Antonio Costa, President of the European Council, as Chief Guests for this year’s Republic Day. During the visit, the India-EU Free Trade Agreement was signed; the EU itself acknowledged that the pact accorded “a significant competitive advantage in key industrial and agri-food sectors”.Prime Minister Narendra Modi’s discussions

with EU leaders laid the groundwork for an extensive and comprehensive partnership in the security sector and other domains. The leaders’ statement noted: “Enhance cooperation to counter terrorism, in all its forms and manifestations including cross-border terrorism...” The term “cross-border terrorism” in such statements indirectly refers to, at a minimum, the infrastructure of terror in Pakistan.In March this year,

External Affairs Minister S Jaishankar visited Brussels. His host was Kaja Kallas, though he also interacted with other senior EU leaders. According to a MEA readout, the visit was “reflective of India’s sustained high-level engagement with the European Union.” It went on to say: “India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum...” Some strange momentum, indeed, if the EU shows a lack of basic sensitivity to India’s significant concerns, as shown during Kallas’ visit to Islamabad.It is a fact that Pakistan’s stock has risen in the world because of its mediation efforts between the US and Iran. Recently, in his reply to an Indian journalist’s question on China-Pak ties, Russian President Vladimir Putin denied that Pakistan was under China’s full control. He went on to say: “Pakistan is a

large country and it has multifaceted ties with different countries.”These assessments of Pakistan should not bother Indian policymakers, but it should worry them when the EU (or, in future, others) makes unwarranted, even if indirect, comparisons of India’s concerns with other global matters. That is where India has to call the EU out — not through smart one-liners but logic backed by action.

The Municipal Corporation of Delhi Commissioner Sanjeev Khirwar inspected various parts of the Civil Lines zone on Tuesday and reviewed the sanitation and pollution control work.

NEWS BOX

Death toll from Philippines quake rises to 46

PHILIPPINES. (Agency)
Rescuers in the southern Philippines pulled a body from the rubble of a collapsed supermarket on Wednesday, as the death toll from a major earthquake climbed to 46.The 7.8-magnitude tremor just off the coast of Mindanao on Monday brought down buildings, triggered landslides and set off tsunami warnings across a swathe of the southern island.Joe Deluvio, 39, was one of two employees at a supermarket in General Santos City that has been the focus of recovery efforts despite the constant threat of aftershocks.Life-detecting equipment had traced a "weak pulse" earlier in the operation, local rescuer Michelle Chua told AFP on Wednesday, but "when they got to the body... there were no signs of life".Deluvio's body was found pinned between two beams, Chua added.The national disaster agency raised the death toll to 45 on Wednesday, while the number of people missing jumped dramatically from four to 17. However, the figure for fatalities did not include Deluvio, the civil defence office confirmed.Most of the additional dead were from Davao Occidental province, and most had been killed in landslides or collapsing buildings, civil defence official Rafaelito Alejandro said in a radio interview.

Indian-Origin Cop Killed In Canada After 18-Year-Old Man Hit Him With Car

Ottawa. (Agency)
An Indian-origin man, working as an officer with the Ontario Provincial Police in Canada, was killed near the town of Hearst while on duty. Provincial Constable Tarun Bali, 29, was seriously injured after he was hit by a vehicle during an investigation and later pronounced dead, according to police.The Ontario Provincial Police (OPP) have arrested an 18-year-old man for the first-degree murder of Bali. The accused has been charged with two counts each of flight from police and dangerous driving.
How Tarun Bali Was Killed
According to OPP Commissioner Thomas Carrique, the accused had escaped from a hospital, where he was being assessed under the Mental Health Act. Officers were trying to apprehend him when the accused allegedly hit Bali with a vehicle. Other police officers later took the accused into custody, Carrique said.The officer said the OPP criminal investigation branch was looking into Bali's death in conjunction with the Office of the Chief Coroner and the Ontario Forensic Pathology Service.
What Canada Police Said
In a statement announcing Indo-Canadian Bali's death, Carrique said, "It is with deep sorrow that I confirm that OPP Provincial Constable Tarun Bali was killed in the line of duty this afternoon in Hearst.""His courage and commitment to serving others will never be forgotten. As we grieve this immeasurable loss, I extend our heartfelt condolences to his loved ones, colleagues and the policing community."Bali was assigned to the Dufferin detachment in southern Ontario and had more than two years of service. Police records showed that he had previously completed rotations in the James Bay detachment area.

Uranium Ban To Site Closures: What US Wants From Iran In Nuclear Talks

MALMÖ. (Agency)
The United States and Iran are currently discussing a possible way forward on Iran's nuclear programme, even as the ceasefire between the two sides remains fragile.Negotiators have narrowed down the talks to four major nuclear issues that will decide whether a broader agreement is possible, according to the NY Times.The first issue is uranium enrichment, where the US wants Iran to stop enrichment for a long period, possibly up to 20 years. Iran has offered a shorter pause of around 10 years, with some reports suggesting a possible middle ground of 15 years.Earlier, US President Donald Trump said even a 20-year ban might not be enough, but later he suggested he could accept it if it was a "real 20 years". It is still unclear whether he would agree to a 15-year deal.Second, both sides are debating what should happen to Iran's existing stockpile of enriched uranium. The US wants it to be reduced or "downblended" under the supervision of international inspectors, while Iran wants to keep control over the material and limit outside involvement.US Secretary of State Marco Rubio has said that any deal must include all of Iran's enriched uranium, about 11 tons. Iran has not clearly said whether it is ready to give up its full stockpile. In an interview with NBC News, Trump had said, "We'll take it out and destroy it, whether it's on site or whether we take it off site."Third, the US wants Iran to completely shut down its three main nuclear sites of Natanz, Fordo and Isfahan. Iran's stockpile of 60 percent enriched uranium is believed to be stored deep underground in Ifsahan. Iran has agreed to close two of these sites, but it wants to keep one site running because it says it still has the "right to enrich uranium" for peaceful purposes. US officials are worried about this idea. In the past, a similar nuclear deal during Barack Obama's time did not fully shut down the Fordo site. Later, Iran restarted activities there, which became a concern again.Officials believe that if even one site remains open, it could still be used in the future for making weapons, especially if it is hidden or underground. At this stage, Iran has not clearly responded to the US demand.The fourth major issue in the talks is international inspections of Iran's nuclear programme. The US wants inspectors from the International Atomic Energy Agency (IAEA) to be able to carry out "snap inspections", meaning they can visit any suspected nuclear site at any time without advance notice.

US blocks Pakistan-China bid to blacklist BLA, Majeed Brigade at UNSC

Islamabad and Beijing had in September last year submitted their joint bid to the Security Council to blacklist the BLA and the Majeed Brigade under the Council's 1267 Al Qaeda Sanctions Committee.

World. (Agency)
The United States has opposed a joint move by Pakistan and China at the UN Security Council to list the Balochistan Liberation Army (BLA) and the Majeed Brigade as a terrorist organisations.Islamabad and Beijing had in September last year submitted their joint bid to the Security Council to blacklist the BLA and the Majeed Brigade under the Council's 1267 Al Qaeda Sanctions Committee.It is learnt that the US, France and UK - all permanent veto-wielding members of the Security Council - blocked the bid this month.Pakistan's Permanent Representative to the UN Ambassador Asim Iftikhar Ahmed had said that terrorist entities,

including ISIL-K, Al-Qaeda, Tehrik-e Taliban Pakistan, East Turkistan Islamic Movement, BLA and the Majeed Brigade operate from Afghan sanctuaries, with more than 60 such terrorist camps serving as hubs for enabling cross-border infiltration and attacks."Pakistan and China have jointly submitted to the 1267 Sanctions Committee a request to designate the BLA and Majeed Brigade. We hope the Council will act swiftly on this listing to curb their terrorist activities," Ahmed had said at a UN Security Council meeting.Pakistan currently sits in the 15-nation Security Council as a non-permanent member for the 2025-26 term, while China is a veto-wielding permanent member of the powerful UN body.Pakistan was the chair of the 1988 Taliban Sanctions Committee of the UN Security Council for 2025, as well as the vice-chair of the Counter-Terrorism Committee.Previously, China, a permanent, veto-wielding member of the UN Security Council, had put on hold

several listing proposals made by India and its partners, like the US, to designate Pakistan-based terrorists and terror entities under the Council's 1267 Al Qaeda Sanctions

(SDGT) designation.The action taken by the Department of State "demonstrates the Trump Administration's commitment to countering terrorism.Terrorist designations play a critical role in our fight against this scourge and are an effective way to curtail support for terrorist activities," the State Department had said.BLA was designated as an SDGT by Washington in 2019 following several terrorist attacks.Since 2019, BLA has claimed responsibility for additional attacks, including by the Majeed Brigade, the State Department had added.The State Department also said that in 2024, BLA claimed it had committed suicide attacks near the airport in Karachi and the Gwadar Port Authority Complex and in 2025, the organisation had claimed responsibility for the March hijacking of the Jaffar Express train travelling from Quetta to Peshawar, killing 31 civilians and security personnel and holding hostage over 300 train passengers.



Committee regime.The US has designated the Balochistan Liberation Army and its alias, the Majeed Brigade, as a Foreign Terrorist Organisation. The State Department added the Majeed Brigade as an alias to BLA's previous Specially Designated Global Terrorist

Pakistani airstrikes in Afghanistan kill at least 13 people, Taliban official says

KABUL. (Agency)
Afghanistan said Wednesday that Pakistan launched new airstrikes targeting the country, killing at least 13 people and wounding 14 others.The countries have engaged in months of fighting that has killed hundreds of people.Taliban chief spokesperson Zabihullah Mujahid said the latest airstrikes targeted the Afghan provinces of Khost, Kunar and Paktika and killed 11 children, one woman and one elderly man.There was no immediate acknowledgment of the strikes from Pakistan.The strikes came a day after suspected Pakistani Taliban militants attacked a security post in the Hasan Khel area of northwestern Khyber Pakhtunkhwa province bordering Afghanistan, triggering an intense gunbattle in which six members of the Federal Constabulary were killed and several others wounded, according to Pakistan's Interior Ministry.Local authorities said Tuesday that security forces killed eight of the attackers and thwarted an attempt to overrun the checkpoint. Interior Minister Mohsin

Naqvi later attended funeral prayers for the dead personnel in Peshawar, the ministry said.Naqvi paid tribute to the dead and expressed condolences to their families, saying their sacrifices would



not be forgotten. He also said Pakistan remained united in its fight against militancy and that operations against groups threatening peace and security would be intensified.Pakistan and Afghanistan have engaged in deadly fighting since late February, when Afghanistan launched a cross-border attack on Pakistan in retaliation for Pakistani airstrikes inside Afghanistan. Pakistan in February declared it was in

open war with its Afghanistan, following a surge in militant attacks on civilians and security forces inside Pakistan. Afghanistan has said a deadly Pakistani airstrikes in March hit a drug-treatment center in Kabul, killing more than 400 people. The death toll could not be independently confirmed.Pakistan has disputed the claim and denied targeting civilians, saying it struck an ammunition depot.The latest development comes months after China hosted peace talks between Pakistan and Afghanistan in Urumqi, in northern China, and later Beijing said Afghanistan and Pakistan had agreed not to escalate their conflict and to explore a solution.Pakistan accuses Afghanistan of harboring militants that carry out deadly attacks inside Pakistan, especially the Pakistani Taliban, known as Tehrik-e-Taliban Pakistan or TTP. The group is separate from, but allied with, the Afghan Taliban, which has ruled Afghanistan since it seized power in the country in 2021 amid the chaotic withdrawal of U.S.-led troops. Kabul denies the charge.

"Disproportionate, Unlawful": Global Rights Bodies On Crackdown In PoK

GENERAL SANTOS.(Agency)
Two major international human rights organisations have issued urgent condemnations of Pakistan's escalating crackdown in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoK), warning that the designation of a peaceful grassroots movement as a terrorist organisation, combined with a lethal military response to civilian protests, represents a grave and accelerating deterioration of fundamental rights in the region.Amnesty International and the International Human Rights Foundation (IHRF) both issued emergency statements on Tuesday, calling for immediate de-escalation, independent investigations into civilian killings, and the unconditional lifting of a ban

imposed on the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee (JKJAAC) - a civil society body that has



led protests over political rights and economic grievances in PoK for several years. What the Rights Bodies Are Saying Amnesty International's Deputy Regional Director for South Asia, Isabelle Lassee, minced no words in her

assessment of Islamabad's actions. "Branding a grassroots organization as 'terrorist' on vague grounds, while simultaneously cutting the region off from the outside world, raises serious concerns regarding the Pakistani authorities' conduct and their disregard for human rights," she said. "The proscription of JKJAAC under anti-terror laws is disproportionate, unlawful and a violation of the right to freedom of association."Lassee further stated that the alarming escalation of violence, including the deaths of protesters, "raises serious questions," and demanded that authorities conduct an independent inquiry into what she described as the alleged extrajudicial killing of JKJAAC activist Shahzeb Habib, as well as the deaths of protesters in Rawalakot.

US, Iran launch airstrikes after Trump blames Tehran for downing Army helicopter

Fighter jets from the U.S. Air Force and Navy conducted the strikes in Iran, the U.S. military's Central Command said, targeting "air defense, ground control stations, and surveillance radar sites."

DUBAI. (Agency)
The U.S. military launched airstrikes and Iran retaliated Wednesday following the crash of an Army helicopter near the Strait of Hormuz that U.S. President Donald Trump blamed on the Islamic Republic.Iran launched attacks in Bahrain and Kuwait, which both sounded alerts and fired air defenses in response. Iran also said it targeted an air base in Jordan hosting U.S. forces, which was not immediately acknowledged either by American or Jordanian officials. Since the U.S. and Israel began striking Iran on Feb. 28, the war has shaken the global economy, driven up energy prices around the

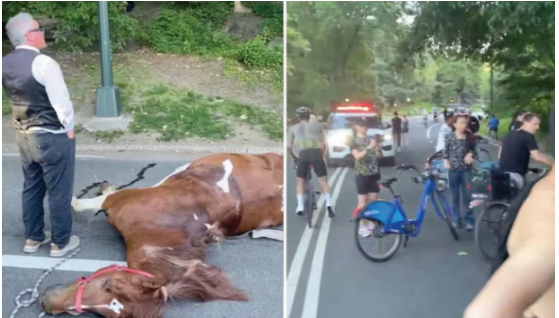
world and made many basics, including food, more expensive.Officials have been unable to turn the April ceasefire into a deal to permanently end the conflict, particularly as Israel intensifies and expands its military campaign in Lebanon against the Iranian-backed militia Hezbollah. Strikes by US and Iran shake the Mideast Fighter jets from the U.S. Air Force and Navy conducted the strikes in Iran, the U.S. military's Central Command said, targeting "air defense, ground control stations, and surveillance radar sites." Iran acknowledged strikes around Bandar Abbas and Qeshm Island, but gave no details on the damage."The operation was a proportional response to recent attacks on U.S. forces and international commercial ships transiting regional waters," Central Command said. Trump said earlier in a social media post that Iran had shot down the aircraft while it was on patrol over the strait and declared that the U.S. "must, of necessity, respond to this attack." Iran's top diplomat said foreign military forces near its territory "are at constant risk" and later vowed that there would be a response to the new U.S. strikes. Iranian forces "will leave no attack or threat

unanswered," Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on X. "Leave our region if you want to be safe."The downing of the Apache attack helicopter and the strikes by



the U.S. military further strained a two-month ceasefire a day after Iran and Israel exchanged fire for the first time since the fragile truce took effect. Iranian state television said Tuesday that the Israeli attacks killed at least two members of the country's air-defense units. **US helicopter collided with Iranian drone, official says** The Army AH-64 Apache attack helicopter went down after colliding with an Iranian drone, according to a U.S. official, who spoke on condition of anonymity to discuss

an ongoing investigation.It wasn't clear whether the collision was intentional, and official statements only said the crash is under investigation. CNN, CBS News and other outlets earlier reported the collision.In the first known operation of its kind by the American military, a drone boat rescued two aviators at 3:30 a.m. local time Tuesday, about two hours after their aircraft went down during a patrol off the coast of Oman, U.S. Central Command said. **Trump said both service members were "safe and uninjured."** The U.S. service members were spotted and picked up by a drone boat that took them to another location on the water, where they were picked up by a helicopter, said Capt. Tim Hawkins, a spokesman for U.S. Central Command. He initially said the drone took the two to shore, and he did not elaborate on the updated timeline.AH-64 Apache helicopters have been a key asset for the American military as it enforces a blockade on Iranian crude oil shipments and tankers, seeking to pressure Tehran into a deal. The helicopters have also been used by the United Arab Emirates to shoot down Iranian drones.



circumstances.Voters For Animal Rights (VFAR), a grassroots nonprofit organisation building political power for animal protection in New York, highlighted that it wasn't the first time a horse has died in the city and demanded urgent action."Tonight, a carriage horse collapsed and died in Central Park. We do not yet know this horse's name, age, history, or what caused their death, but we do know this: no horse should spend their life pulling a carriage through the streets of Manhattan," the organisation stated."This moment demands more than outrage. It demands action. On Thursday, the City Council will reintroduce Ryder's Law — legislation to finally transition New York City away from horse carriages and retire the horses to sanctuaries."Similarly, PETA demanded that the city council immediately pass the Ryder's Law to ensure safety of the horses. "City Council, what more do you need? Central Park goers are crying and hugging after seeing this traumatizing death for all involved," PETA said.



Nora Fatehi's

FIFA World Cup 2026 Song Siir Siir Is Out; Star Opens Up About Indian Representation

Nora Fatehi's latest song Siir Siir, created in collaboration with music producer Sanjoy and French singer VegeDream, is officially out now. The track is part of the official music project for the FIFA World Cup 2026 and features on the tournament's official album which brings together artists from different musical backgrounds across the world. The release marks a major international milestone for Nora.

Speaking about the song, Nora said, "This is song is a very special one for me. Through Siir Siir, we wanted to try and blend different cultural influences and create something that feels truly global yet unique. I really wanted to bring together every part of my identity, from my Moroccan roots, to my Canadian roots as well as the huge influence India has had on me with all the love I have received from the country and the South Asian community at large – which has been so instrumental in my journey."

She added, "What makes this song even more meaningful is the strong Indian representation behind the scenes, from the choreographer and dancers to the styling team, everyone played a huge role in bringing this vision to life. Creating this song for a global event like the FIFA World Cup 2026 for me is almost unreal! It feels like a full-circle moment where different cultures, sounds and people come together. In my own way I hope I am able to bring the amazing sounds of the East to the world."

What makes the project special is its strong Indian connection. A large part of the music video team, including the choreographer, dancers and stylists, is Indian. While Nora Fatehi has been expanding her international career for years, being associated with the FIFA World Cup for a second time puts her back on one of the world's biggest stages and further boosts her global profile.



'Pankha Leke Khada Hawa De Raha Tha': Bharti Singh Recalls ROFL Story About Madhuri Dixit's Son From RRRPK Set



Madhuri Dixit, Triptii Dimri and Dharna Durga, who were busy promoting their latest release, Maa Behen, recently graced comedian Bharti Singh and her husband Haarsh Limbachiya's YouTube channel. During the candid and fun interaction, Bharti and Haarsh recalled a hilarious anecdote from the sets of Karan Johar's Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, where Madhuri's son Arin and Arbaaz Khan's son Arhaan Khan were working as assistant directors.

Recalling their surprise at discovering that Madhuri Dixit and Dr Shriram Nene's son was working as an assistant director on the project, Haarsh shared that Karan Johar had invited them to film the Dhanalakshmi advertisement sequence featured in the movie. He said, "Vahan par Madhuri ma'am ka beta assist kar raha hai aur humko nahi pata. Ek sundar sa, pyaara sa ladka aaya aur pankha leke khada hawa de raha tha. Maine kaha nahi nahi beta, it's okay. Fir Karan sir aaye, 'he's Madhuri's son' (There, Madhuri ma'am's son was assisting on set and we had no idea. A sweet, good-looking young boy came over and stood there holding a fan, fanning us. I told him, 'No, no beta, it's okay.' Then Karan sir came and said, 'He's Madhuri's son')."

To this, Bharti added that they got nervous after Karan informed them that he was Arin, Madhuri's son. She added, "Uska pankha theek chal raha tha, humara andar se ulta ghumne lag gaya. Humari saari garmi chali gayi. Humari hawa tight ho rahi thi. Jab Karan sir ne btaaya, hum dono khade hogye (His fan was working perfectly, but inside, our heads started spinning. We became nervous and flustered. The moment Karan sir told us who he was, both of us immediately stood up)."

Haarsh added, "Humne pauna ghanta usko bola ki rehne do, but woh bhi karke hi gaya, hawa deke hi gaya. Main soch raha arey please yaar mat kar (For nearly 45 minutes, we kept telling him not to bother, but he still insisted on doing it and continued fanning us. I was thinking, 'Please, yaar, don't do this')."

Bharti also revealed that they were surprised to see Arhaan Khan bringing a chair for them.

'There Was Arjun Kapoor...': Farah Khan Reveals She Choreographed Sonam Kapoor's Sangeet As Her Wedding Gift



Filmmaker and choreographer Farah Khan recently made a surprising revelation on her YouTube channel. The director revealed that she had choreographed the entire sangeet ceremony of Bollywood actress Sonam Kapoor's wedding as a special marriage gift for the actress.

The revelation was made during a recent episode of Farah Khan's YouTube vlog featuring actor-dancer Shantanu Maheshwari and reality show star Shruti Sinha. During their conversation, Shruti recalled assisting Farah at Sonam Kapoor's wedding festivities, which led to the choreographer to share an interesting behind-the-scenes anecdote.

Speaking about the event, Farah said, "At Sonam Kapoor's wedding, my wedding gift was that I would choreograph the sangeet."

She further recalled how her longtime assistant Firoz, along with Shruti, had worked alongside her during the preparations for the grand celebration.

"So, Firoz, my old assistant was with me, and I think Shruti came with Firoz."

She added, "There was Sonam, there was Arjun Kapoor, there was Masaba, there was Rhea Kapoor, Jacqueline Fernandez... everyone was being taught by Shruti."

The conversation took a nostalgic turn when Shruti remembered being praised by Farah during the hectic rehearsals. Shruti revealed that Farah had singled her out as one of the best assistants on the team while several celebrities were busy rehearsing for their performances. "There were two assistants, and I remember Farah Ma'am scolding the other one a lot. Pointing at me she said, 'this girl is doing well, everyone follow this girl', recalled Shruti.

For the uninitiated, Sonam Kapoor tied the knot with businessman Anand Ahuja on May 8, 2018, in Mumbai. The wedding was one of the most talked-about celebrity events of the year and was attended by the who's who of Bollywood. The sangeet ceremony saw Bollywood bigwigs like Karan Johar, Salman Khan, Anil Kapoor, Arjun Kapoor set the stage on fire. Talking about Farah Khan, she remains one of Bollywood's most celebrated choreographers and filmmakers.

Shraddha Kapoor

And Director Laxman Utekar's Biopic Eetha Locks Release Date

Shraddha Kapoor's upcoming biographical drama Eetha has officially locked its release date. Directed by filmmaker Laxman Utekar, the film is expected to bring an inspiring real-life story to the big screen, with Shraddha stepping into a challenging and emotionally demanding role. The film is all set to hit the screens on this Raksha Bandhan, i.e August 28.



Trade Analyst Taran Adarsh announced the film and its release date, '#Xclusiv... DINESH VIJAN – LAXMAN UTEKAR REUNITE: SHRADDHA KAPOOR STARS IN 'EETHA' – RELEASE DATE LOCKED... Following the blockbuster success of #Chhaava, Dinesh Vijan and Laxman Utekar reunite for #Eetha – a bold and emotionally charged film that features #ShraddhaKapoor in a powerful, author-backed role. The release date has been locked:

28 Aug 2026 [#RakshaBandhan]. The film also features #RandeepHooda and #MohdZeeshanAyyub in pivotal roles."

Shraddha Kapoor reportedly wrapped up shooting for Eetha in May. The much-anticipated biopic is based on legendary Tamasha artiste Vithabai Narayangaonkar. The film, which focusses on her extraordinary journey between 1940 and 1990, concluded its shoot with a grand montage song sequence filmed in Bhor, Maharashtra.

As reported by Mid-day, on May 5, the makers reached its finish line with a massive montage song, featuring Kapoor and a crowd of 800 people, shot in Bhor, Maharashtra. "The final song has a montage that chronicles the journey of Shraddha's character from a young woman to her brush with fame and finally how she falls on hard times. Like the remaining numbers, this too has been choreographed by Vaibhavi Merchant," said a source. The portal also informed that it was the end of the 60-day schedule that began in March. The team shot in Madh Island in Mumbai, Solapur, Aundhewadi, Satara, and Nashik.

In November, 2025, Shraddha Kapoor started shooting for Eetha. Directed by Laxman Utekar, the project marks Shraddha's first collaboration with the filmmaker and is being produced by Dinesh Vijan's Maddock Films.

